उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के अधिकारों व सवालों पर व गन्ना आपूर्ति श्रृंखला को जिम्मेदार बनाने के लिये

उत्तर प्रदेश लघु एवं सीमांत गन्ने किसानों की मांगे

उत्तर प्रदेश, देश में गन्ना की खेती में अग्रिनी भूमिका अदा करता है जिसमें बड़े किसानों के साथ-साथ तकरीबन ***95%*** लघु एवं ***67%*** सीमांत किसान आजीविका के लिये मुख्यतः गन्ने की खेती में निर्भर करते हैं। गन्ने की खेती में बड़ी संख्या में महिला किसान एवं अन्य राज्यों से खितहर मजदूर भी शामिल रहते हैं। अतः खेत से ले कर अंततः चीनी के इस्तेमाल से खाने-पीने की वस्तुओं के तैयार होने तक की श्रृंखला में मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने एवं गन्ना आपूर्ति श्रृंखला को जिम्मादार बनाने की अत्यंत आवश्यकता है, जिसमें सामाजिक संगठनों से ले कर, चीनी मिलों, स्थानीय पेरु, सरकार, शोध संस्थानों, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य महिला आयोग आदि की महती भूमिका है। अतः गन्ना आपूर्ति श्रृंखला को जिम्मेदार बनाने के उद्देश्य से निम्न मांगों को शामिल किया गया है जिसे सरकार एवं अन्य घटकों के समक्ष रखा जाएगा।

उत्तर प्रदेश में, गन्ना किसानों व मजदूरों के अधिकारों के संबंध में किसान समूह, महिला किसान संगठन व सामाजिक संगठनों के तरफ से निम्न मांगें हैं:

1. सप्लाई टिकिट का आवंटन करते वक़्त छोटे किसानों व महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाये।
2. गन्ना तौल सेंटर पर उनके गन्ने के तौल में महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाये।
3. जिन महिला किसानों के पति प्रवास कर गए हैं और जमीन उनके पति या ससुर के नाम है तो गन्ना क्रय केन्द्रों पर उस महिला किसानों से गन्ना खरीदा जाये।
4. गन्ना तौल सेंटर पर महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग अलग स्वच्छ पीने का पनि, शौचालय आदि की व्यवस्था की जाये।
5. छोटे महिला गन्ना किसानों के गन्ने की खरीददारी सीधे उनके खेत से की जाये।
6. महिला मजदूरों के साथ लिंग के आधार पर मजदूरी में किसी भी प्रकार से भेद -भाव न की जाये। इसके लिए श्रम विभाग को जिम्मेदार बनाते हुये उन्हे सक्रिय किया जाए।
7. एक बार जारी किए गये सप्लाइ टिकिट/ पर्ची की वैध्यता पूरे पेराई सत्र के लिए मान्य की जाये।
8. गन्ना की खेती के दौरान किसी भी प्रकार से बाल मज़दूरों व बन्धुआ मजदूरों के इस्तेमाल पर रोक लगाया जाये। इसके कड़ाई से पालन के लिए जिलाधिकारी को जबावदेय बनाया जाए।
9. गन्ना खरीददारी पर पैसों का भुगतान शीघ्र अति शीघ्र ***14*** दिन के भीतर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किया जाये। और देर होने पर प्रति वर्ष ***12%*** के दर से भुगतान ब्याज़ के साथ किया जाये।
10. गन्ना की खरीददारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हीं किया जाये और प्रति वर्ष इसमें इनपुट कॉस्ट को ध्यान में रखते हुये इसकी बढ़तोरी की जाये।
11. गन्ना किसानों के मुद्दों के निपटारे के लिए एक ग्रीवान्स रिड्रेसल सेल की स्थापना की जाये और इसे सक्रिय किया जाये। इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो ताकि महिलाओं के मुद्दो को समझा जा सके।
12. सप्लाइ टिकिट से ले कर गन्ना तौल तक सभी सरकारी अधिकारी पुरुष हीं होते हैं। महिला किसानों के हितों के मद्दे नजर इन सभी जगहों पर महिला अधिकारियों को नियुक्त किया जाए।
13. पंचायतों के जैसे ही गन्ना समितियों में महिलाओं की सदस्यता बढाई, तथा उनका आरक्षण कम से कम ***33%*** तक सुनिश्चित किया जाये।

14. गन्ना के गट्ठर का अधिकतम वजन ***50*** किलो से ज्यादा न हो ऐसा सुनिश्चित किया जाये जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन द्वारा निश्चित किया गया है।

अगर गन्ना किसानों एवं मजदूरों के अधिकारों व हितों के संबंध में कोई सुझाव व मांग रखना चाहते हों तो कृपया हमसे **friendsofoxfam@oxfamindia.org** पर संपर्क करें।

On the rights of sugarcane farmers in Uttar Pradesh and to make sugarcane supply chain responsible

Demands of Small and Marginal Sugarcane Farmers of Uttar Pradesh

Uttar Pradesh plays a leading role in the cultivation of sugarcane in the country. 95% small and 67% marginal farmers along with large farmers depend mainly on sugarcane cultivation for their livelihood. A large number of women farmers and agricultural labourers from other states are also involved in sugarcane cultivation here. There is an urgent need to ensure human rights and make the sugarcane supply chain responsible from the farm to the final use of sugar in the preparation of foods and beverages. The role of social organizations, sugar mills, local authorities, government, research institutes, State Commission for Protection of Child Rights, State Commission for Women, etc. is critical. Therefore, in order to make the sugarcane supply chain responsible, the following demands have been included, which will be placed before the government and other departments.

The demands from farmers' groups, women farmers' organizations, and social organizations regarding the rights of sugarcane farmers and labourers in Uttar Pradesh are enlisted below:

1. While allotting the supply ticket, priority should be given to small farmers and women farmers.

2. Priority should be given to women farmers in weighing their sugarcane at the sugarcane weighing centre.

3. In case a woman farmer's husband has migrated and the land is in the name of her husband or father-in-law, then sugarcane should be purchased from that woman farmer at the sugarcane purchasing centre.

4. At the sugarcane weighing center, separate clean drinking water, toilets etc. should be arranged for women and men.

5. Sugarcane from small-scale women farmers should be purchased directly from their fields.

6. Women labourers should not be discriminated against in terms of wages, on the basis of gender. For this, the labour department should be responsible and active.

7. The validity of the supply ticket/slip once issued should be valid for the entire crushing season.

8. Use of child labourers and bonded labourers should be banned in all forms during the cultivation of sugarcane. The District Magistrate should be made accountable for its strict compliance.

9. Payment of money on sugarcane purchase should be made as soon as possible within 14 days as per the directions of the Hon'ble High Court. And in case of delay, it should be paid with interest at the rate of 12% per annum.

10. Procurement of sugarcane should be done only at the minimum support price and it should be increased every year keeping in mind the input cost.

11. A Grievance Redressal Cell should be established and activated for redressal of the issues of sugarcane farmers. Women should be represented in this so that the issues of women can be understood.

12. From the supply ticket issuing official to the sugarcane weighing official, all government officials are men. Keeping in view the interests of women farmers, women officers should be appointed in all these places.

13. The membership of women in sugarcane committees as in Panchayats should be increased; reservation should be ensured to at least 33%.

14. It should be ensured that the maximum weight of the bundle of sugarcane is not more than 50 kg, which has been fixed by the International Labour Organization.

If you want to make any suggestion or demand on the rights and in the interest of sugarcane farmers and labourers, please contact us at friendsofoxfam@oxfamindia.org